

‘लंगड़े बारात के घोड़े,’ ‘रेस हॉर्स’ बनना चाहते हैं’

राहुल की इस शिकायत से कई पुराने नेता अति नाखुश, पर बेबस हैं

– रेणु मित्तल –
– राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो –
नई दिल्ली, 4 जुलाई। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के उन जनरलों (वरिष्ठ नेताओं), जिन्होंने वर्षों तक वफादारी और समर्पण के साथ पार्टी की सेवा की है, के प्रति असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें “लंगड़े घोड़े” कहा, जो अब बूढ़े, बीमार और संगठन के लिए बेकार हो चुके हैं, जिन्हें अब हटा कर “चरागाह” में भेज दिया जाना चाहिए। इस पर पार्टी के अंदर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई।

पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस टिप्पणी से न केवल आहत हैं, बल्कि गुस्से और दुख से भी पर उठे हैं। पार्टी से लंबे समय से जुड़े मझोले स्तर के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी की भाषा और शब्दों के चयन को घमंड से भरा तथा एक नेता के लिए अनुपयुक्त करार दिया।

एक अन्य कार्यकर्ता ने यह पूछ लिया कि क्या वे (राहुल) यही शब्द अपनी माँ और बहन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक ने रिटायरमेंट ले लिया है और दूसरी को कुछ वर्षों से कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है।

जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी

■ पर इतना जरूर हुआ है कि दबी जुबान से सवाल भी पूछे जाने लगे हैं, राहुल गांधी के बारे में।

■ जब राहुल, पुराने “अनफिट” नेताओं के रिटायरमेंट की बात करते हैं तो सोनिया गांधी का नाम लेने लगे हैं लोग, क्योंकि वे काफी असें से बीमार चल रही हैं, पर आखिरी निर्णय में उनकी काफी चलती है।

■ जिन लोगों को राहुल रिटायर देखना चाहते हैं, उनमें कमलनाथ, अशोक गहलोत, भूपेन्द्र हुड्डा का नाम ऊपर ही ऊपर है।

■ जो, अपने आप रिटायर कर दिये गये उनमें टॉप में नाम हैं जनार्दन द्विवेदी का, जनार्दन द्विवेदी एक तरह से सोनिया गांधी के “मेंटर” जैसे थे, पर, उन्होंने अकारण एक स्टेटमेंट दे दिया कि राजीव गांधी ने उनसे कहा था कि दोनों भाई-बहन में प्रियंका ज्यादा उपयुक्त हैं, राजनीति के लिए। इस वक्तव्य के बाद वो कांग्रेस के रंगमंच से गायब से ही हो गये थे।

■ इसी प्रकार गहलोत, हाईकमान के खिलाफ बगावत करने के कारण, “साइड लाइन्ड” हैं और लगातार कोशिशों के बावजूद, “एंट्री” नहीं पा सके हैं।

की कमान संभाली है, पार्टी में नेताओं की तीन श्रेणियां उभर कर सामने आईं

हैं: वे, जिन्हें दरकिनार कर दिया गया है, वे जिन्हें जबरन रिटायर कर दिया गया

है, और वे, जो पार्टी के संचालन के तौर-तरीकों से नाखुश होकर पार्टी छोड़ गये हैं।

सबसे पहला नाम, जिसकी चर्चा पार्टी में होती है, वह है प्रियंका गांधी का। वे हाईकमान का हिस्सा मानी जाती हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें एक तरह से निष्क्रिय कर दिया है। वे कहने को तो एआईसीसी की महासचिव हैं, लेकिन उनके पास न कोई विभाग है, न कोई जिम्मेवारी। उनके करीबी लोग पार्टी पदों से हटा दिए गए हैं और अन्य लोग भी उनसे दूर हो गए हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि प्रियंका उनके करियर में कोई मदद नहीं कर सकती।

ऐसे नेताओं की सूची लंबी है। जनार्दन द्विवेदी, जिन्हें सोनिया गांधी का राजनीतिक गुरु तक माना जाता था, ने एक बार सार्वजनिक रूप से कह दिया था कि राजीव गांधी ने उनसे कहा था कि प्रियंका गांधी राजनीति में राहुल से अधिक उपयुक्त हैं तथा वे राजनीति में अच्छा काम कर सकती हैं। उसी दिन से द्विवेदी का पतन शुरू हो गया और वे पूरी तरह हाशिए पर चले गए।

अशोक गहलोत, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तथा तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोचिंग विद्यार्थियों की आत्महत्या पर सुनवाई जुलाई के अंत में

जयपुर, 4 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों के आत्महत्या करने से जुड़े मामले में सुनवाई जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में रखी है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंगान पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अवलत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में समान मामला लंबित बताया जा रहा है। वहां 17 जुलाई को

■ सुप्रीम कोर्ट का इस बिंदु पर रुख स्पष्ट होने तक हाई कोर्ट ने सुनवाई टाली।

सुनवाई होनी है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उच्च शिक्षा को लेकर मामला सुन रहा है या कोचिंग छात्रों के बिंदु पर प्रकरण की सुनवाई कर रहा है।

ऐसे में 17 जुलाई को होने वाली सुनवाई के बाद इसकी स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। इसलिए प्रकरण की सुनवाई जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में करना उचित होगा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘भगवान को न्याय में देखें जजों में नहीं’

–जाल खंभाता–
–राष्ट्रदूत नई दिल्ली–
नई दिल्ली, 4 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लोगों से यह सलाह दी कि वे भगवान को न्यायाधीशों में न ढूंढ़ें बल्कि न्याय में ढूंढ़ें। जस्टिस एमएम सुंद्रेश ने यह टिप्पणी उस समय की, जब एक वकील ने कोर्ट में कहा, “जज हमारे लिए भगवान की तरह होते हैं।”

न्यायमूर्ति सुंद्रेश ने स्पष्ट किया कि न्यायधीश सिर्फ विनम्र सेवक होते हैं और उन्होंने कहा, “हम में भगवान की न तलाश करें, न्याय में भगवान की तलाश करें। हम केवल विनम्र सेवक हैं।”

■ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुंद्रेश ने एक मामले की सुनवाई के दौरान उस समय यह टिप्पणी की जब वकील ने कहा कि जज हमारे लिए भगवान की तरह होते हैं।

यह टिप्पणी एक वकील द्वारा एक नोटिस पर आपत्ति जताए जाने के बाद आई, जिसमें यह दावा किया गया था कि वकीलों ने न्यायधीशों को फिक्स किया था। वकील ने उस नोटिस को “अपमानजनक” बताया।

जस्टिस सुंद्रेश ने कहा, कृपया भावुक न हों। जज के तौर पर हमें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता।।

पिछले साल, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी यह स्पष्ट (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सात हाईकोर्ट्स में 3 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने दो दिन तक 54 उम्मीदवारों का इटरव्यू लेकर यह नियुक्तियां की हैं

– जाल खंभाता –
– राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो –
नई दिल्ली, 4 जुलाई। न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने इस सप्ताह की शुरुआत में दो दिन तक 54 उम्मीदवारों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार किया। उसके बाद 7 उच्च न्यायालयों में जजों के रूप में पदोन्नति के लिए रिपोर्ट 36 मामलों को मंजूरी दी। इसके साथ ही देशभर के 25 उच्च न्यायालयों में 1,122 स्वीकृत पदों के मुकाबले 371 रिक्तियों में से कुल 90 पद भर दिए गए हैं।

जिन उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए नाम मंजूर किए गए हैं, उनमें दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पटना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान सहित कई न्यायालय शामिल हैं।

कोलीजियम के प्रस्ताव के

■ इन 36 जजों में से दो जज राजस्थान हाईकोर्ट के लिए चयनित हुए हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट व मध्यप्रदेश में दस-दस, तेलंगाना व गौडारी हाईकोर्ट में 4-4, दिल्ली हाईकोर्ट में तीन तथा पटना हाईकोर्ट में दो जज नियुक्त किए गए हैं।

■ कोलीजियम ने इस बार नियुक्ति के लिए साक्षात्कार का विकल्प चुना है, बजाय दस्तावेजों की जांच के। जिन अर्थार्थियों का साक्षात्कार हुआ उनमें न्यायिक अधिकारी व वरिष्ठ वकील शामिल हैं।

अनुसार, पंजाब एवं हरियाणा और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों में 10–10, तेलंगाना और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों में 4–4, दिल्ली उच्च न्यायालय में 3, राजस्थान और पटना उच्च न्यायालयों में 2–2 तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 नाम की सिफारिश की गई है।

कोलीजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, और वरिष्ठ

पहल एक स्थायी बदलाव को दर्शाती है, जिसमें केवल दस्तावेजी समीक्षा की पारंपरिक प्रणाली से हटकर अब प्रत्यक्ष संवाद और सक्रिय मूल्यांकन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। पहले की प्रणाली में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, राज्य सरकारों, केंद्रीय विधि मंत्रालय और खुफिया ब्यूरो की रिपोर्टों को प्रमुखता दी जाती थी, जबकि नई प्रक्रिया में उम्मीदवारों के साथ सीधे संवाद को ज्यादा महत्त्व दिया गया है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि ये साक्षात्कार सुप्रीम कोर्ट की पारंपरिक गर्मी की छुट्टियों के दौरान आयोजित किए गए, जिन्हें अब “आंशिक कार्य दिवस” के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस दौरान जहां न्यायिक पीठों ने अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई की, वहीं प्रशासनिक व संस्थागत कार्य, जैसे नियुक्तियां आदि, भी सक्रिय रूप से जारी रहे।

बिहार के एस.आई. आर. के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस

नयी दिल्ली, 04 जुलाई। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को चुनौती देते हुए इसके खिलाफ वह उच्चतम न्यायालय जायेगी।

कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया लगभग दो करोड़

■ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के स्पेशल इन्टेंसिव रिवीजन से दो करोड़ मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। यह राष्ट्रीय मसला है इसलिए पार्टी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी।

मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश है।

पार्टी सूत्रों ने आज यहां बताया कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

